

छात्रा से नैक टीम को जानकारी मिली कि छात्रा को पंद्रह दिनों बाद पता करने बोल रहा विश्वविद्यालय माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर नैक टीम ने लगा दी क्लास

इंचार्ज से पूछा-आखिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनते कितने दिनों में है?

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शनिवार को नैक टीम का तीन दिनी निरीक्षण पूरा हो गया। नैक टीम स्टूडेंट की सुविधाओं को बारीकी से देखती रही। इसी कड़ी में शुक्रवार को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के मामले में नैक टीम ने इंचार्ज की क्लास लगा दी। दरअसल, डीएसडब्ल्यू में चर्चा के दौरान नैक टीम

के सदस्यों का सामने युनिवर्सिटी पहुंची एक छात्रा से हो गया। सामान्य पूछताछ में छात्रा ने बताया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अधिकारी और संबंधित विभाग पंद्रह दिनों बाद पता करने आने को बोल रहे हैं। इस पर टीम ने डीएसडब्ल्यू इंचार्ज से पूछा कि आखिर यहां माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता कितने दिनों में है? टीम ने डीएसडब्ल्यू में एक अधिकारी से >> श्रेष्ठ पेज 5 पर



नैक टीम के सदस्य डीएसडब्ल्यू में छात्रों से सुविधाओं को लेकर जानकारी ले रहे थे। इसी समय उनकी नजर पड़ी की छात्र पीछे वाले गेट से आ रहे हैं। छात्रों ने बताया कि सामने का गेट बंद रहता है। इस बात को टीम ने भी देखा। इस पर इंचार्ज से पूछताछ की। साथ ही नैक टीम ने पूछ लिया कि दिव्यांग छात्र आ जाए तो रैम्प कहाँ है? इस पर बताया गया कि रैम्प सामने के गेट की ओर बना है। इस पर हैरान टीम ने रविशंकर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से पूछा कि सामने को गेट बंद करके रखे हैं और रैम्प सामने बना होना बता रहे हैं, ये कैसा विरोधाभास है?

डीएसडब्ल्यू में दिव्यांग के लिए रैम्प कहाँ है?

छात्रों लाइब्रेरी में जगह की कमी बताई

निरीक्षण के दूसरे दिन नैक टीम ने छात्रों से विवि में मिल रही सुविधाओं के विषय में फीडबैक लिया था। नैक की तीन टीम ने छात्रों से चर्चा की थी। इस दौरान छात्रों ने लाइब्रेरी में जगह की कमी बताई। कहा कि संख्या बढ़ने से बैठने में दिक्कत आती है। वहीं पीएचडी स्कालर्स ने मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। बताया कि वर्तमान में 10 हजार मिलता है। इसे बढ़ाया जाए।

प्रथम पेज के शेष

माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर...

पूछा कि दिव्यांगों के लिए रैम्प कहाँ है? यह भी सवाल किया कि पीछे हिस्से से क्यों प्रवेश देते हैं?

इस संबंध में जानकारी के अनुसार नैक पियर टीम ने अंतिम दिन आजाद हॉस्टल आईव्यूएसी सेल, रीजनल स्टडी एंड रिसर्च, राष्ट्रीय सेवा योजना विंग, हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। टीम के मेम्बर सुबह आजाद हॉस्टल पहुंचे, वहां स्टूडेंट से चर्चा भी की। पास स्थित रिसर्च हॉस्टल और गांधी हॉस्टल में टीम नहीं गई। पॉवर ग्रिड हॉस्टल का भी टीम ने निरीक्षण किया। टीम मेम्बर परिसर में स्थित बंजारी माता मंदिर भी दर्शन के लिए गए।

बैठक के वापस हुए रवाना - दोपहर 12 बजे तक निरीक्षण के बाद नैक टीम वापस प्रशासनिक भवन पहुंची। वहां टीम की कुलपति समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। तीन दिन के निरीक्षण में आई बातों पर चर्चा के बाद में नैक पियर टीम के वापस रवाना होने की खबर है।

स्टूडेंट की बातें सुनी ध्यान से - छात्रों की सुविधाओं को देखने शुक्रवार को नैक की टीम डीएसडब्ल्यू में चली गई। वहां टीम मेम्बर ने एक छात्रा से पूछा कि वह किस काम से आई है। छात्रा ने बताया कि माइग्रेशन के लिए आई है। तब टीम ने पूछा कि काम हो गया, इस पर छात्रा ने जवाब दिया कि पंद्रह दिन बाद आकर पता कर लेना कह रहे हैं। इस पर टीम ने पूछा कि इंचार्ज कौन है? इंचार्ज से पूछा कि

आखिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता कितने दिनों में है। सामने का गेट बंद रहने पर भी सवाल किए। उधर, जानकारों ने बताया कि माइग्रेशन की प्रक्रिया दो दिन में हो सकती है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर चालान पटाना होता है।

छात्रों ने दी रविवि को आंदोलन की चेतावनी

खराब रिजल्ट को लेकर रविवि पर लगे आरोप, सौंपा ज्ञापन

धरसीवा। पं. श्यामचरण शुक्ल शासकीय महाविद्यालय धरसीवा के छात्रों ने अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन में आ रही समस्या की शिकायत को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले प्रदर्शन करते तहसीलदार को उच्च शिक्षा मंत्री व रविवि कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व धरसीवा विधानसभा अध्यक्ष देवेन्द्र खेलवार ने किया। ज्ञापन में जल्द से जल्द उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग की गई। रविवि पर आरोप लगाते हुवे कहा कि प्रदेश भर में रविशंकर विश्वविद्यालय का यह ऐसा पहला



सत्र होगा जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम बेहद ही खराब आया है। जिसका कारण रविवि वदारा लापरवाही पूर्वक उत्तरपुस्तिकाओं की जांच है। जो छात्र छात्राये एक विषय में पूरक आये हैं उन्हें पुनर्मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की

समस्याएँ नहीं हो रहीं है किंतु जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, वे पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय को चेतावनी देते हुए कहा की यदि उनकी यह माँग जल्द से जल्द पूरा नहीं होती है तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा।